

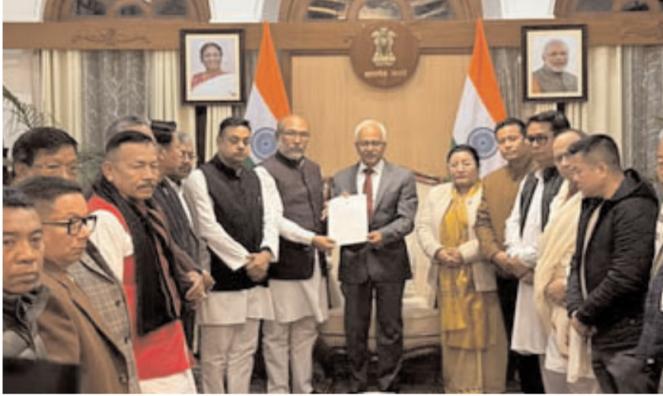


मिटी चीफ

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा

नहीं संभला मणिपुर...

इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने रविवार शाम को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पिछले साल के अंत में राज्य में जातीय हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने जनता से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि यह पूरा साल बेहद खराब रहा। मैं राज्य के लोगों से तीन मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे इसका दुख है। पिछले तीन-चार महीनों में शांति की स्थिति देखकर मुझे उम्मीद है कि 2025 में राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। राज्यपाल को सौंपे गए अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, मैं नौगंधोम्बम बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। मणिपुर के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मैं केंद्र सरकार अत्यंत आभारी हूँ, जिन्होंने समय पर कार्यवाही, हस्तक्षेप, विकास कार्य और विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया, ताकि मणिपुर के हर एक नागरिक के हित की रक्षा की जा सके।



मेरी केंद्र सरकार से ईमानदार अपील है कि वे इसी तरह काम जारी रखें। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ- मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखा जाना चाहिए, जिसका हजारों वर्षों का समृद्ध और सभ्य इतिहास है। सीमा पर घुसपैठ रोकी जानी चाहिए और अवैध प्रवासियों को देश से

बाहर करने की नीति बनाई जाए। नशे और नशे के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाना चाहिए। एमएफआर की कड़ी और पूरी तरह से सुशिक्षित नई व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिसमें बायोमेट्रिक जांच सख्ती से की जाए। सीमा पर समयबद्ध और तेजी से काम जारी रहना चाहिए।

हिंसा के चलते दबाव में थे बीरेन सिंह

राज्य में मई 2023 से जातीय हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। नवंबर में मणिपुर के जिरिबाम में तीन महिलाओं और उनके तीन बच्चों की हत्या के बाद भी बवाल हुआ। राज्य में लगातार हो रही हिंसा के चलते एन बीरेन सिंह भारी दबाव में थे और उनको पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही थी। एनडीए की सहयोगी एनपीपी ने भी मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और नेतृत्व परिवर्तन करने की मांग की थी।

इस तरह शुरू हुई हिंसा

मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच हिंसा पिछले साल तीन मई को उस समय शुरू हुई थी, जब मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आदिवासी छात्रों संघ ने एक रैली आयोजित की थी, जिसमें मणिपुरी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद से राज्य में हिंसा का सिलसिला जारी है, और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा।

रेबीज पीड़ितों को इच्छामृत्यु का अधिकार मिलेगा या नहीं? फैसला आज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट रेबीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु के अधिकार की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एनजीओ ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल की याचिका पर 10 फरवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। शीर्ष अदालत ने 2020 में केंद्र को नोटिस जारी कर 2019 में दायर याचिका पर स्वास्थ्य

और पर्यावरण मंत्रालयों से जवाब मांगा था। याचिका में, एनजीओ ने मांग की है कि रेबीज रोगियों के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उन्हें या उनके अभिभावकों को सहायक मृत्यु या निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए चिकित्सकों की सहायता लेने का विकल्प चुनने की अनुमति मिल सके। 19 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि जीवन के अधिकार में

मरने का अधिकार भी शामिल है और 'लिविंग विल' बनाने की अनुमति देकर निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैधानिक बना दिया था। इसके तहत असाध्य रूप से बीमार या स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था (पीवीएस) में पड़े उन रोगियों को चिकित्सा उपचार या जीवन रक्षक प्रणाली से इन्कार करके सम्मानजनक तरीके से विदा लेने का अवसर दिया जा सकता है, जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है।

विश्व हिंदू परिषद की अपील- अंग्रेजी में शपथ न लें दिल्ली के नए विधायक

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने अपील की है कि दिल्ली विधानसभा के लिए चुना गया कोई भी विधायक इस बार अंग्रेजी में शपथ न ले। विहिप ने अनुरोध किया है कि सभी नवनिर्वाचित विधायक अपनी-अपनी मातृभाषा (संस्कृत, हिंदी या गुरुमुखी पंजाबी) में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। संगठन ने इसे अपनी मातृभाषा को मजबूत करने और राष्ट्रीयता का प्रतीक बताया है। दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए अधिकतर विधायक हिंदीभाषी हैं, जबकि कई विधायक सिख हैं। विहिप के अनुसार, अपनी मातृभाषा में शपथ लेने से उसका सम्मान बढ़ेगा और यह लोगों में भारतीयता के बोध को बढ़ावा देगा। अब तक अनेक विधायक

अंग्रेजी में शपथ ग्रहण करते रहे हैं। विहिप ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। दिल्ली की जनता ने आप पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। संगठन को आशा है कि विधायक जनता के इस प्रेम और विश्वास को संजोकर रखेंगे। विहिप ने उम्मीद जताई है कि नए विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। संगठन ने एक अपील जारी कर कहा कि इस कार्य काल का शुभारम्भ मांगलिक रीति नीति और शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। विहिप का मानना है कि मातृभाषा का सम्मान और प्रचार-प्रसार देश की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

महाकुंभ में महाजाम: 15 से 20 किमी लंबे जाम में फंसे रहे लाखों श्रद्धालु

प्रयागराज। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ के कारण एक बार फिर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं संगम रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया। महाकुंभ स्नान का रविवार को 28वां दिन था। संगम में सुबह से ही भक्तों की भीड़ स्नान के लिए उमड़ी। इसके चलते संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 15 से 20 किमी लंबा जाम लगा गया। लोग 20 किमी पैदल चलकर भी संगम तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में माइक से ऐलान हुआ कि जहां जो घाट दिखे वहीं स्नान करो और लौट जाओ। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे थककर बेहाल हो गए। पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज शहर के सभी एंट्री प्वाइंट बंद कर दिए गए। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने-जाने वाले रास्तों पर 25 किमी तक गाड़ियां रेंग रही थीं। संगम में डूबकी लगाने जाने वालों और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भूखे-प्यासे जाम खुलने का इंतजार कर रहे थे। लखनऊ से प्रयागराज के रास्ते पर नवाबगंज से (करीब 20 किमी) जाम लगा। झुंसी की तरफ से सराय इनायत से 15 किमी का जाम लगा। वाराणसी से आने वाले लोग इसी रास्ते से आते हैं।



रीवा रोड पर गौहनिया से भीषण जाम

रीवा रोड पर गौहनिया से भीषण जाम रहा। नैनी के पुराने पुल से इसकी दूरी करीब 16 किमी थी। आलम यह था कि रीवा शहर के पहले ही पुलिस ने लोगों को रोक दिया। लोग 12 घंटे से ज्यादा समय तक वाहनों में फंसे रहे। महाकुंभ में जाने और लौटने वाले अलग-अलग राज्यों के लोग फंसे रहे। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी रविवार को रीवा से प्रयागराज जाने वाले थे, लेकिन लंबी जाम के कारण वे कुंभ नहीं जा सके। एमपी-यूपी बॉर्डर पर सुबह करीब 7 बजे से वाहनों को कतार लग गई। प्रशासन और जनप्रतिनिधि व्यवस्था बनाने में लगे रहे। यह दूसरी बार है जब बॉर्डर पर महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु जाम में फंसे। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज से 300 किमी पहले कटनी में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्तों को बंद करवा दिया। कटनी पुलिस लोगों से वापस लौटने की अपील करती रही। लाखों श्रद्धालु जहां थे वहीं फंस गए।

रोहित शर्मा ने फ्लॉप शो पर लगाया फुल स्टॉप... तोड़ा सचिन और द्रविड़ का रिकॉर्ड

कटक। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 'फ्लॉप शो' पर फुल स्टॉप लगा दिया है। वे फॉर्म में लौट आए हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने रविवार को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच में तूफानी सेंचुरी ठोकी। उन्होंने बतौर ओपनर उतरने के बाद 76 गेंदों में 9 चौकों और 7 छक्कों के दम पर शतक कंप्लीट किया। उन्होंने सिक्स लगाकर सेंचुरी पूरी की। यह उनके वनडे करियर का 32वां शतक है। रोहित ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है। दरअसल, रोहित वनडे



में सबसे कम पारियों में 32 शतक तक पहुंचने वाले दूसरे प्लेयर हैं। रोहित ने 259

वनडे पारियों में यह आंकड़ा छुआ। सचिन ने 283 पारियों में 32 वनडे शतक लगाए थे। विराट कोहली टॉप पर हैं, जिन्होंने 194 पारियों में यह कारनामा अंजाम दिया। 37 वर्षीय रोहित सलामी बल्लेबाज के रूप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। वे अभी तक 15,350 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने सचिन को पछाड़ा, जिन्होंने बतौर वनडे ओपनर 15335 रन जुटाए। लिस्ट में टॉप पर पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। सहवाग ने 16119 रन जोड़े हैं। रोहित ने 30 की उम्र के बाद भारत के

लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन को पछाड़ा है। वे 36 सेंचुरी जड़ चुके हैं। सचिन ने 30 की उम्र के बाद 35 शतक मारे थे। रोहित ने इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 प्लेयर्स की लिस्ट में एंट्री कर ली है। उन्होंने द्रविड़ को 11वें स्थान पर धकेल दिया। हिटमैन के खाते में 267 वनडे मैचों में 11000 से ज्यादा रन हैं। वहीं, द्रविड़ ने 344 वनडे में 10889 रन बटोरे। फेहरिस्त में टॉप पर सचिन हैं, जिन्होंने 18426 वनडे रन बनाए। श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर कुमार संगकारा (14234) दूसरे और विराट

कोहली (13911) तीसरे नंबर पर हैं। रोहित साथ ही वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। गेल फिलहाल 337 सिक्स उड़ा चुके हैं। गेल ने अपने करियर में 331 छक्के मारे। रोहित और गेल से आगे पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी हैं, जिन्होंने 351 सिक्स ठोके। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या (279) चौथे और पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (229) पांचवें नंबर पर काबिज हैं।

शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को नगर निगम जबरदस्ती देगा नई दुकानें

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। शिवाजी मार्केट की 126 दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम यहां के दुकानदारों का विस्थापन करने के लिए मशक्कत कर रहा है, लेकिन दुकानदार वहां से दुकानें खाली करने को तैयार नहीं हैं। नंदलालपुरा में बनाए गए नए मार्केट में दुकानें आवंटित करने के लिए पहले भी लॉटरी का आयोजन किया गया था, जिसमें सात दुकानदार ही पहुंचे। अब दूसरा आयोजन सोमवार को होगा, जिसमें नहीं आने वाले दुकानदारों के नाम से भी लॉटरी किसी भी व्यक्ति की मदद से निकाली जाएगी। बरसों पुराने शिवाजी मार्केट में 126 दुकानदार हैं और उन्होंने निगम के आला अधिकारियों से लेकर जन प्रतिनिधियों तक को ज्ञापन देकर मांग की है कि उन्हें कोई अन्य स्थान पर जगह दी जाए, क्योंकि नंदलालपुरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया



मार्केट पूरी तरह फेल है। वहां तीसरी मंजिल पर दुकानें आवंटित की गईं तो वहां व्यापार ही खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर दुकानदार नए मार्केट में शिफ्ट होने के मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं। गत दिनों सिटी बस ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के

कार्यालय में दुकानदारों को नए मार्केट में दुकानें आवंटित करने के लिए लॉटरी का आयोजन किया गया था, इसमें सभी दुकानदारों को सूचना पत्र भेजकर बुलवाया गया था, मगर केवल सात दुकानदार ही इस प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे थे।

शेष दुकानदारों ने वहां पहुंचकर लॉटरी का बहिष्कार कर विरोध जताया था। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को अंतिम बार लॉटरी का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शेष बचे दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने के

लिए लॉटरी खोली जाएगी। इसकी सूचना भी सभी दुकानदारों को भेजी गई है।
व्यापारी एसोसिएशन की यह है आपत्ति
शिवाजी मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय केशुनिया के मुताबिक जिस जगह हमें शिफ्ट किया जा रहा है वहां मार्केट तीन-चार मंजिला है। हमारी कपड़े, बेल्स, मछली दाना, खिलौने, बैग, रेडीमेड गारमेंट, पशियों के पिंजरे जैसे सामानों की दुकानें हैं। इन दुकानों को यदि पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया तो वहां हमें दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। सचिव गयूर खान के मुताबिक हमारी दुकानों के पीछे कान्ह नदी की गंदगी बहती है। लेकिन दुकानों की आड़ में दिखाई नहीं देती। नगर निगम के पास नदी के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कोई योजना नहीं है। अफसर हमें किसी भी हालत में यहां से शिफ्ट करने पर तुले हैं, इससे कोई

प्रोजेक्ट सफल नहीं होने वाला है, हमारा नुकसान जरूर हो जाएगा। ...तो बच्चों से खुलवा देंगे लॉटरी नगर निगम के अपर आयुक्त नरेंद्र पांडे के मुताबिक सोमवार को अगर दुकानदार लॉटरी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनके नामों की लॉटरी किसी आम व्यक्ति अथवा बच्चों से खुलवा दी जाएगी और आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद निगम के अफसर मार्केट खाली कराने की प्रक्रिया को अंजाम देंगे।
रोड किनारे से कान्ह नदी के होंगे दर्शन
शिवाजी मार्केट की 126 दुकानों को तोड़ने के बाद राजवाड़ा के पास रामबाग पुल से कृष्णपुरा पुल के बीच लोग कान्ह नदी को रोड पर खड़े होकर निहार सकेंगे। निगम रिबर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत निगम मुख्यालय के सामने शिवाजी मार्केट की दुकानों को हटाना चहता है। इन दुकानों के हटने के बाद कान्ह नदी को लोग

सड़क पर खड़े होकर निहार सकेंगे।
यह है रिबर फ्रंट प्रोजेक्ट
रिबर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम द्वारा नदी किनारे के 3.91 किलोमीटर हिस्से को विकसित किया जाएगा। वर्ष 2018 से यह प्रोजेक्ट संचालित हो रहा है और विगत चार साल में रिबर फ्रंट फेज 1, फेज 2, फेज सात के हिस्से का काम पूरा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत हुए कार्यों के बाद संजय सेतु, हरसिद्धि, हरिराव होलकर छत्री के पास जयरामपुर पुल से गणगौर घाट तक के हिस्से में नदी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। अभी कबूतरखाना, कर्बला से जयरामपुर, मच्छी बाजार वाले नदी किनारे हिस्से में करीब एक हजार मकान व झोपड़ियां अतिक्रमण कर बनी हुई हैं। निगम द्वारा इन्हें भी शिफ्ट करने की योजना है। इसके बाद ही नदी के 3.91 किलोमीटर हिस्से में लोग सड़क किनारे खड़े नदी के सौंदर्य को निहार सकेंगे।

किसी एक दुकान से किताबें, यूनिफार्म खरीदने की बाध्यता नहीं... कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला

स्कूलों की मनमानी खत्म होगी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूलों की मनमानी खत्म करने के लिए बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कई नियमों में बदलाव किया है जिससे पैरेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टर ने कॉपी, किताबों और यूनिफार्म की अनिवार्यता में एकाधिकार खत्म करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश से स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं की मनमानी भी समाप्त होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो स्कूल के प्राचार्य, संचालक और प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्य दोषी माने जाएंगे। आदेश के अनुसार, सभी स्कूल संचालक/प्राचार्य को अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कक्षा की अनिवार्य पुस्तकों की सूची और यूनिफार्म की जानकारी परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले अपलोड करनी होगी। इसके अलावा, इस सूची को विद्यालय परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना भी अनिवार्य होगा।

हर स्कूल की अपनी वेबसाइट होना अनिवार्य

किसी भी छात्र या अभिभावक को किसी विशेष विक्रेता या संस्थान से किताबें, कॉपीयां या यूनिफार्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान्यता नियमों के अनुसार, हर स्कूल की अपनी वेबसाइट होना अनिवार्य है। विद्यालय संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश के समय और परीक्षा परिणाम के दौरान, अभिभावकों को पुस्तक सूची की एक प्रति प्रदान की



जाए। इसके अलावा, कम से कम तीन विक्रेताओं के नाम सत्र शुरू होने से एक माह पूर्व वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। परीक्षा से पहले अगली कक्षा की किताबों के लिए दबान न डालें परीक्षा से पहले अगली कक्षा की किताबें खरीदने का दबाव नहीं डाले सकते स्कूल संचालक/प्राचार्य विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अभिभावक 30 अप्रैल 2025 तक किताबें खरीद सकते हैं। साथ ही, सीबीएसई, आईसीएसई, एमपीबीएसई और अन्य शैक्षणिक बोर्डों के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पालक शिक्षक बैठक के दौरान विद्यालय संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी निजी प्रकाशक, मुद्रक या विक्रेता स्कूल परिसर में अपने उत्पादों का प्रचार न कर सके। किसी भी स्थिति में पुस्तकों के सेट में अनावश्यक सामग्री जोड़े जाने पर रोक लगाई जाएगी, ताकि छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न

पड़े।
पूरा सेट खरीदना भी जरूरी नहीं
किसी भी विक्रेता को पूरे सेट की अनिवार्यता नहीं होगी, बल्कि विद्यार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार केवल आवश्यक किताबें खरीदने की स्वतंत्रता होगी। यदि कोई छात्र पुरानी किताबों का उपयोग करना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी।
तीन साल तक नहीं बदलेगी यूनिफार्म
यूनिफार्म के संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि कम से कम तीन वर्षों तक यूनिफार्म में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ताकि अभिभावकों पर आर्थिक भार न पड़े।
नोटबुक (कॉपी) पर ग्रेड, साइज, पृष्ठ संख्या और मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
किताबों या कॉपियों पर स्कूल का नाम मुद्रित नहीं होगा
किसी भी स्कूल की किताबों या कॉपियों पर स्कूल का नाम मुद्रित नहीं किया जाएगा और ना ही इन पर चढ़ाए जाने वाले कवर पर विद्यालय का नाम अंकित किया जाएगा।

आज से बीएसएफ के 800 शूटर दिखाएंगे अपनी सटीक निशानेबाजी

इंदौर। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के श्रेष्ठ निशानेबाज सोमवार से इंदौर में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता में बीएसएफ की सभी फ्रंटियर्स से 800 से अधिक निशानेबाज भाग लेने के लिए इंदौर पहुंच चुके हैं। यह 52वीं इंटर-प्रेंटियर प्लाटून वेपन शूटिंग प्रतियोगिता 2024-25 भाग लेंगे। इसमें बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ महिला



निशानेबाज भी शामिल होंगी। सोमवार सुबह 9-40 बजे रेवती रेंज पर बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी

(डीजी) मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। यह प्रतियोगिता 10 से 15 फरवरी तक चलेगी। छह दिवसीय इस

आयोजन में 11 प्लाटून हथियार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें से 10 प्रतियोगिताएं रेवती रेंज में और 51 एमएम मोर्टार की एक प्रतियोगिता महू स्थित हेमा रेंज में होगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नई प्रतिभाओं की पहचान और चयन करना है, ताकि वे भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व कर सकें और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी कर सकें।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट... उद्योगपतियों के लिए इंदौर से भोपाल तक बनेगा कॉरिडोर

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। भोपाल में होने वाली दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी सरकार और प्रशासन तैयारियों पर बारीकी से नजर रखा हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट पर भोपाल एयरपोर्ट की अपेक्षा अधिक कनेक्टिविटी है। इस वजह से अधिकतर उद्योगपति इंदौर एयरपोर्ट आकर कार से भोपाल का रास्ता कवर करेंगे। उन्हें भोपाल तक पहुंचाने के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त शिवम वर्मा ने शहर के उद्योगपतियों से चर्चा की। चर्चा के दौरान शहर के उद्योगपतियों ने कहा कि निवेश के लिए जो भी उद्योगपति बाहर से मग्न आ रहे हैं। उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होना चाहिए। यदि आते ही उन्हें ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था मिल गई तो पहला प्रभाव ही गलत चला जाएगा। इस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि उनके आने पर कॉरिडोर बनाने पर विचार हो रहा है। इंदौर से भोपाल तक उनके जाने के लिए विशेष व्यवस्था का जाएगी।



मालवी अंदाज में होगा स्वागत
चर्चा में बताया गया कि इंदौर में उद्योगपतियों का स्वागत मालवी अंदाज में होगा। साफा या पगड़ी पहनाई जाएगी और इंदौर के स्थानीय व्यंजनों से उनका मुंह मीठा करवाया जाएगा। इसके बाद उन्हें भोपाल के लिए रवाना किया जाएगा। मग्न आने वाले उद्योगपतियों के लिए ऊजैन महाकाल दर्शन के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। मग्न के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर ले जाने के लिए भी मग्न पर्यटन विभाग खास व्यवस्थाएं करेगा। पहली बार इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में हो रही है, इसलिए भोपाल के आसपास के पर्यटक स्थलों पर भी उन्हें ले जाने के लिए रोडमैप बनाया जाएगा।

भोपाल में मग्न की विरासत, भव्यता को दर्शाने वाली गैलरी बनाई जाएगी। इस गैलरी को कई कलाकार मिलकर तैयार करेंगे। इसमें मग्न की संस्कृति, विरासत और अन्य पहलुओं से जुड़े भव्य दृश्य होंगे जिन्हें उद्योगपतियों को दिखाया जाएगा। मग्न में खानपान के लिए इंदौर सबसे ज्यादा मशहूर है। कोई कार्यक्रम हो और इंदौर के खानपान की बात न हो यह ही नहीं सकता। भोपाल में दो दिन तक चलने वाले इस भव्य आयोजन के लिए इंदौर के प्रमुख शोफ का एक टीम तैयार की जाएगी। मालवा के व्यंजनों को पेश करने के लिए पाक कला में माहिर शोफ इंदौर से भोपाल जाएंगे।

मोबाइल टॉवर के पास लगी भीषण आग, हॉस्टल में मच गया हड़कंप

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। शहर के राजीव गांधी चौराहे के पास पिपल्सराव स्थित एक बहुमंजिला इमारत में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। यह आग मोबाइल टावर के पास से शुरू हुई और धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। इमारत में एक छात्रावास और नीचे एक कमर्शियल फैक्ट्री संचालित हो रही थी। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत

दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तेजी से आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। फायर कर्मियों ने बताया कि आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। जिस समय आग लगी उस समय छात्रावास में कई छात्र मौजूद थे। आग की लपटें और धुएं को देखते ही छात्र घबरा गए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। स्थानीय लोगों ने भी छात्रों को बाहर निकालने में

मदद की। नीचे स्थित कमर्शियल फैक्ट्री में भी कई लोग काम कर रहे थे, जो समय रहते बाहर निकल गए। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी संतोष कुमार दुबे ने बताया कि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हालांकि पूरी जांच के बाद ही सही कारण स्पष्ट होगा। हालांकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने 10-10 करोड़ हर्जाना मांगा

यशवंत क्लब सचिव और पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि नोटिस

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी और यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष परमजीत छाबड़ा उर्फ पम्मी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने मानहानि नोटिस जारी किया है। राकेश सिंह ने कहा कि दोनों ने शालीनता की सारी हदें पार करते हुए कुलीनों के संस्कारों की धज्जियां उड़ाते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित किया। राकेश सिंह यादव ने शासकीय लीज की भूमि पर बने यशवंत क्लब की

अनियमितताओं के संदर्भ में सवाल पूछा था जिस पर दोनों ने जवाब नहीं दिया और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी और पूर्व अध्यक्ष परमजीत छाबड़ा उर्फ पम्मी ने पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव के संदर्भ में बयान जारी करके कहा की यादव खुद को हैसियत देखें। इंदौर शहर के दस लोग भी नहीं पहचानते, कांग्रेस के पांच कार्यकर्ता भी साथ नहीं हैं। सस्ती लोकप्रियता और घटिया राजनीति करते हैं। घटिया और ओछी सोच है। पूर्व

प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि उन दोनों के इस कृत्य से छवि को नुकसान हुआ और उनके समर्थकों में रोष है। यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर ही मेरे 45 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस पर मेरे समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन बातों को षड्यंत्र पूर्वक अखबारों में एक तरफा प्रकाशित किया गया और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया गया।
15 दिन में माफी मांगने को कहा
इस संपूर्ण घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव

राकेश सिंह यादव ने यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी और यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष परमजीत छाबड़ा उर्फ पम्मी पर दस-दस करोड़ की मानहानि नोटिस जारी किया है। इसके साथ 15 दिन का समय समस्त अखबारों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से माफी मांगने के लिए दिया है। यादव ने कहा कि अगर 15 दिन में माफी नहीं मांगी गई तो न्यायालय में संविधान की धाराओं के अंतर्गत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

कांग्रेस नेता यादव ने कहा था कि इंदौर का यशवंत क्लब अब शराबी, जुआरियों, सटोरियों सहित भूमिफिया की शरणस्थली बन गया है। किसी जमाने में कुलीनों का यशवंत क्लब आज सरकारी कलाली का अहाता बन गया है। यादव ने मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव को लेटर लिखा जिसके साथ यशवंत क्लब की विस्तृत रिपोर्ट भी पहुंचाई। यादव ने मांग की है कि यशवंत क्लब का खेल विभाग के अंतर्गत अधिग्रहण कर फर्म एवं सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाना चाहिए।

कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव के अनुसार यशवंत क्लब में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड को आईडीसीए में सौंपा जाना चाहिए। वर्तमान में आईडीसीए के पास क्रिकेट खिलाड़ी तैयार करने के लिए खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में इंदौर में क्रिकेट खिलाड़ियों का भविष्य चौपट हो रहा है। यशवंत क्लब में मौजूद टेनिस, स्कैश, बॉस्केट बॉल, बैडमिंटन जैसी खेल सुविधाओं का उपयोग शराबी, भूमिफिया अपने मनोरंजन के लिए करते हैं।

मोतीनगर में अतिक्रमण पर चला सरकार का बुलडोजर, 110 दुकानों को हटाया

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। राजधानी भोपाल के मोतीनगर क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई 110 दुकानों को प्रशासन ने रविवार को हटा दिया है। सुबह 5 बजे शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक चली। इस दौरान पुलिस ने चारों तरफ से एक किमी दूर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही में रोक लगा रखी थी। हालांकि 12.30 बजे बैरिकेडिंग हटा दी गई। कार्रवाई के दौरान बस्ती हटने को लेकर विरोध करने वाले कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को हाउस अरेस्ट किया गया था। मोती नगर के 110 दुकानों को हटाने से पहले सुभाषनगर ब्रिज को भी बंद कर दिया था। मीडिया को भी इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी। कार्रवाई के दौरान 10 जेसीबी, 2 बड़ी पोक्लेन, 25 डंपर, 10 ट्रैक्टर ड्राली, 50 लोडिंग गाड़ियां लगाई गईं। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और रेलवे के करीब 1000 अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे। 200 से अधिक पुलिसकर्मी रहे



तैनात कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। रचना नगर, रायसेन रोड, सुभाष नगर और बोगदा पुल की तरफ बैरिकेडिंग की गई। किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। बैरिकेडिंग तीन लेयर पर की गई थी। जबकि सुभाष नगर ब्रिज के दोनों तरफ पुलिस तैनात रही। ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। कार्रवाई के दौरान 4 एसडीएम, 4 तहसीलदार, 10 नायब

तहसीलदार, 10 राजस्व निरीक्षक, 50 पटवारी, 50 कोटवार तैनात किए गए। 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस दौरान रास्ता बंद होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस लोगों को वापस लौटा रही थी। कार्रवाई के दौरान हंगामे की थी आशंका कार्यवाही के दौरान सुभाष नगर आरओबी को भी बंद कर दिया गया था। अधिकारियों को डर था

कि कार्रवाई के दौरान हंगामे की स्थिति बन सकती है। ऐसे में ब्रिज के ऊपर से भी पत्थरबाजी होने की संभावना थी। इसलिए दोनों ओर से ब्रिज पर पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए। मोती नगर बस्ती के पास में ही एक मैरिज गार्डन भी है। यहां आज सगाई का कार्यक्रम होना है। लड्डुकी पक्ष के लोग बाहर पहुंचे थे इसलिए उनकी गाड़ियां बैरिकेडिंग के पास में ही रुकवा दी गईं। पुलिस उन्हें अपने साथ

मैरिज गार्डन तक लेकर गईं। साथ आए कैमरामैन की भी जांच की गई। उसके बाद ही आगे जाने दिया गया। 384 मकान को भी हटाया जाएगा गौरतलब है कि सुभाषनगर ब्रिज की थर्ड लेन और रेलवे की थर्ड लाइन के लिए यहां के 384 मकान और 110 दुकानों को तोड़ा जा रहा है। दुकानें हटा दी गई हैं। आगामी दिनों में मकानों को तोड़ा जाएगा। वहीं इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। हंगामा होने की संभावना के चलते पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। इससे पहले 6 फरवरी को पुलिस मौके पर पहुंची थी और लोगों को सामान हटाने का अल्टीमेटम दिया था। अफसरों की समझाइश के बाद कई दुकानदारों ने अपना सामान हटा लिया था। इतने अधिकारी मौके पर रहे मौजूद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रविवार को कार्रवाई के लिए एसडीएम एलके खरे, डॉ.

अर्चना रावत, रविशंकर राय और रवीश श्रीवास्तव की ड्यूटी लगाई गई। चार तहसीलदार आलोक पारे, कुनाल राउत, दिलीपकुमार चौराया और चंद्रकुमार ताम्रकार समेत 10 नायब तहसीलदार, 10 राजस्व निरीक्षक, 50 पटवारी और 50 कोटवारों को भी तैनात किया गया था। मोती नगर राजनीतिक नफरत की भेंट चढ़ा कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को सुबह 7.45 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक कोहेफिजा टीआई ने टीम के साथ नजरबंद करके रखा। मनोज शुक्ला ने कहा कि मोती नगर राजनीतिक नफरत की भेंट चढ़ गया है। भाजपा सरकार ने मोतीनगर तोड़कर भोपाल की गंगा-जमुना तहजीब को कलंकित कर दिया है। दरअसल मोतीनगर बस्ती को हटाए जाने का विरोध कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला लगातार विरोध कर रहे थे। वे कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन भी दे चुके थे। अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोध

किया था। इसके चलते ही शुक्ला को नजरबंद किया गया। कार्रवाई के दौरान ऐसी रही प्रशासन की व्यवस्था -रचना नगर, रायसेन रोड, सुभाष नगर और बोगदा पुल की तरफ बैरिकेडिंग की गई। किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। -बैरिकेडिंग तीन लेयर पर की गई थी। सुभाष नगर ब्रिज के दोनों तरफ पुलिस तैनात रही। ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। -कार्रवाई के दौरान 4 एसडीएम, 4 तहसीलदार, 10 नायब तहसीलदार, 10 राजस्व निरीक्षक, 50 पटवारी, 50 कोटवार तैनात किए गए। -200 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। बता दें कि 4 फरवरी तक बस्ती खाने करने का समय था, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं मिलने की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। दो दिन तक कार्रवाई अटकी रही। फिर अगले 2 दिन तक लोगों ने स्वेच्छा से सामान हटाना शुरू कर दिया।

आदिवासी लीडरशिप के लिए कांग्रेस देगी 7 दिवसीय प्रशिक्षण

इंटरव्यू से 120 आदिवासी युवाओं का किया चयन

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हर वर्ग के लोगों को दोबारा कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने कांग्रेस के कोर वोटर्स को अपनी पार्टी से दोबारा जोड़ना चाहत हैं। इसके लिए आदिवासी लीडरशिप विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस आदिवासी लीडरशिप कार्यक्रमों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ने वाले मप्र के 89 आदिवासी ब्लॉक से आदिवासी युवा महिला-पुरुष भोपाल पहुंचे। इनका एआईसीसी और एमपी कांग्रेस के ट्राइबल डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के जरिए 120 आदिवासी युवा चयनित हुए। अब इनका सात दिनों का प्रशिक्षण मोहनखेड़ा में 19 फरवरी से शुरू होगा गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पहली बार आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आवासीय ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। धार जिले के मोहनखेड़ा में 19 फरवरी से 25 फरवरी तक यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आदिवासी वर्ग के युवाओं को पार्टी से जोड़ने और चुनावी रणनीति के हिसाब से तैयार करने के लिए कांग्रेस आदिवासी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है।

आदिवासी इस देश का है मालिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रशिक्षण शिविर एवं साक्षात्कार के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित प्रदेश के सभी जिलों से आए आदिवासी वर्ग पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश का मालिक है, जल-



जंगल और जमीन पर सबसे पहला अधिकार आदिवासी वर्ग का है। आदिवासी वर्ग के महापुरुषों चाहे वो बिरसा मुंडा हो, टंट्या भील हो या रघुनाथ शाह-शंकरशाह हो या वीरगंगा रानी दुर्गावती हो इन सभी ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया और आदिवासी वर्ग की रक्षा और सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने में महती भूमिका का निर्वहन किया।

जातिगत जनगणना से हर वर्ग को मिलेगा लाभ

पटवारी ने कहा कि देश की युवा शक्ति लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना से हर वर्ग के मध्यम और गरीबों को उसका लाभ मिलेगा। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता का अवसर मिलेगा। आदिवासियों का और कांग्रेस का और संविधान का प्रकृति का आपस में गहरा रिश्ता है जो हमें जल-जंगल से ही मिला है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जीवन के लिए हवा और जल

हैं उससे ही हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आक्सीजन और ऊर्जा मिलती है।

आदिवासी वर्ग की महिलाओं को किया जा रहा गायब

पटवारी ने कहा कि आदिवासी वर्ग के लिए डेढ़ लाख से अधिक बेकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। आदिवासियों की जमीन मप्र सरकार और इनके नुमाइंदों और सरकार के चापलूस अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। आदिवासी वर्ग को कभी बांध के नाम पर कभी संचुरी के नाम पर जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। दलितों और आदिवासियों पर भाजपराज में अत्याचार और अन्याय की घटनाएं चरम पर हैं। आदिवासी वर्ग की महिलाओं को गायब किया जा रहा है जो सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है। आदिवासी वर्ग के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आदिवासी वर्ग के छात्रावास जर्जर अवस्था में हैं, ग्रामीण अंचलों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा और शिक्षकों का अभाव है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले कांग्रेसियों ने खराब सड़कों पर रोपे बेशरम के पौधे

भोपाल। राजधानी में आगामी 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भोपाल एयरपोर्ट से लेकर मानव संग्रहालय तक सड़कें बनाई जा रही हैं। शहर के मुख्य मार्गों का नए सिरे से रेनोवेशन कर रंगाई-पुताई और पौधारोपण किया जा रहा है। शहर के दूसरे हिस्सों की खराब सड़कें न बनाए जाने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र

में खराब सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ बेशरम के पौधे रोपे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सड़क पर बेशरम के पौधे रोपने के बाद मीडिया से कहा-सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करा रही है। इस मीट में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश-विदेश के तमाम उद्योगपति भोपाल आएंगे। सबका भोपाल में स्वागत है। लेकिन, सरकार इस आयोजन को लेकर भोपाल के नागरिकों

के साथ भेदभाव कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया। गोविंदपुरा विधानसभा के महात्मा गांधी चौराहे से पिपलानी पेट्रोल पंप तक कांग्रेसियों ने खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया और बेशरम के पौधे लगाए। इस प्रदर्शन में गोविंदपुरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रविन्द्र साहू झूमरवाला नजर नहीं आए।

हमीदिया अस्पताल में स्वीकृति के बाद भी नहीं शुरू हो पाई रोबोटिक

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में स्वीकृति के बाद भी रोबोटिक सर्जरी शुरू नहीं हो पाई है। रोबोटिक सर्जरी लिए 35 करोड़ रुपए बजट भी मिल चुका है। लेकिन इस यूनिट को अभी तक तैयार नहीं किया जा सका है, जिससे जटिल आपरेशन की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। अभी तक यह सुविधा सिर्फ बड़े निजी अस्पतालों में है। हालांकि अस्पताल के जिम्मेदारों का कहना है कि जल्द ही यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसे लेकर तैयारियों की जा रही है। रोबोटिक सर्जरी करने वाला हमीदिया मध्य प्रदेश का पहला शासकीय अस्पताल होगा। अभी तक प्रदेश के एक भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं है। जबकि निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी करवाने का खर्च अधिक होता है। इस कारण यहां गरीब और मध्यमवर्गीय लोग सर्जरी नहीं करवा पाते हैं। हमीदिया अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से इस वर्ग को राहत

मिलेगी। साथ ही रोबोटिक सर्जरी का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलने लगेगा। काफी समय से चल रही है तैयारी जानकारी के लिए बता दें कि हमीदिया अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी को लेकर करीब एक साल ले ज्यादा समय से तैयारी चल रही है। रोबोटिक सर्जरी के लिए पहले से ही वार्ड तैयार किया जा चुका है। यह आम सर्जरी वार्ड से बड़ा है। इसके लिए डाक्टरों का भी चयन किया जा चुका है, जिन्हें रोबोटिक सर्जरी के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। यहां यूरोलाजी, हेड एंड नेक कैंसर, गायनिक सर्जरी, जनरल सर्जरी आदि में इससे मरीजों को सुविधा मिलने लगेगी। यह होती है रोबोटिक सर्जरी रोबोटिक सर्जरी कंप्यूटराइज्ड डिवाइस से की जाएगी, जो चिकित्सक के सहयोगी के रूप में काम करेगी। इसमें सर्जरी के दौरान चिकित्सक रोबोटिक सेटअप का रिमोट हाथ में पहनते हैं। इसमें लगे कैमरे और सेंसर रोबोट घुटने

के सारे मूवमेंट और स्थिति को नोट कर उसकी थ्रीडी इमेज तैयार करते हैं। थ्रीडी इमेज के हिसाब से रोबोट सर्जरी का सटीक प्लान तैयार करता है। वह चिकित्सक को बताता है कि हड्डी कितनी खराब है, कितनी और किस जगह से काटने पर क्या परिणाम आ सकते हैं। आपरेशन एक विशेष कंसोल में बैठा सर्जन आपरेशन का काम संभालता है। सर्जन को आपरेशन करने वाली जगह का एक बड़ा 360 डिग्री दृश्य दिखता है। इसके अलावा साथ खड़ा चिकित्सक इस बात की जानकारी देता है कि उपकरण सही जगह पर जाकर अपना काम कर रहा है। जल्द शुरू करने का दावा हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनित टंडन ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी को लेकर तैयारी आखिरी पड़ाव पर है। जल्द ही इसे शुरू करने की तैयारी है। जल्द ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। रोबोटिक सर्जरी को लेकर काम काफी समय से चल रहा है।

मप्र में फरवरी माह में पहली बार दो जिलों का पारा 5 डिग्री से नीचे

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश में आ रहे ठंडी हवा ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। प्रदेश में फरवरी माह में पहली बार दो जिलों का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। शनिवार-रविवार रात में शहडोल का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अशोकनगर में 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, भोपाल समेत 17 शहरों में ठंड बढ़ गई और तापमान 10 डिग्री के नीचे रहा। हालांकि, सोमवार से मौसम में फिर से बदलाव होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, अब दिन-रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

शीत प्रभाव वाले जिले-

शहडोल, अशोकनगर, मंडला, नौगांव, पचमढ़ी, सिंगरौली शीत प्रभाव वाले जिले रहे। वहीं कम शीत प्रभाव वाले जिले - उमरिया, खजुराहो, राजगढ़, शाजापुर, ग्वालियर, अनूपपुर, मलांजखंड, सतना, जबलपुर, नीमच, सतना, टीकमगढ़, रीवा रहे। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से कम वाले शहर शहडोल 4.6, अशोकनगर 4.8, मंडला 5.8, नौगांव 6.0, पचमढ़ी 6.8, सिंगरौली 6.9, उमरिया 7, खजुराहो 7.2, राजगढ़ 7.6, शाजापुर 7.6, ग्वालियर



8, अनूपपुर 8.6, मलांजखंड 8.7, सतना 9, जबलपुर 9.5, नीमच 9.6, सतना 9.6, टीकमगढ़ 9.7, रीवा 9.8, रायसेन 10, दमोह 10, गुना 10.2, भोपाल 10.6, निवाड़ी 10.6, शिवपुरी 10.9, सीहोर 11.2।

पांच दिन से बढ़ी ठंड

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में बर्फबारी होने से प्रदेश में भी ठंड का असर बढ़ा है। पिछले पांच दिन से दिन-रात के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। भोपाल, शहडोल, राजगढ़, शाजापुर, उमरिया, खतरपुर, सिंगरौली, टीकमगढ़, मंडला, रायसेन, गुना, सतना, सीधी, दमोह, रीवा और नर्मदापुरम जिले ठिठुर गए।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मेहमान चखेंगे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। राजधानी भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारी तेजी से की जा रही है। 24 और 25 फरवरी को राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मेहमानों, डेलिगेट्स और अन्य का लंच खास होगा। विदेशी मेहमानों को प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखाने की योजना है। यहां तीन अलग-अलग कैटेगरी में भोजन की व्यवस्था रहेगी। इसमें वीवीआईपी (मंत्री,

विदेश और देश के बड़े बिजनेसमैन), वीआईपी-मीडिया और अन्य डेलीगेट्स के लिए खाने के डोम अलग-अलग होंगे। यहां पर खाने का मेनू मेट्रिक्स एक जैसा रहेगा। इन तीनों कैटेगरी के मेनू में भारतीय और विदेशी व्यंजन दोनों होंगे, जिनमें कॉन्टिनेंटल और ओरिएंटल फूड्स के साथ-साथ मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में तीन कैटेगरी में खाने की व्यवस्था की गई है। इसमें तीन अलग-अलग डोम बनाए जा रहे



है। यह तीनों डोम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे। पर्यटन विकास निगम भोजन की पूरी व्यवस्था कर रहा है। 125 लोगों की टीम दो दिन मेहमानों के लिए लंच तैयार करेगी। वीवीआईपी डोम में खाना खाने की व्यवस्था बैठ कर रहेगी। वहीं, बाकी दो कैटेगरी में बुफे होगा। खाना सर्व करने और व्यवस्था के लिए 200 लोग रहेंगे। विदेश से आने वाले मेहमानों को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र की स्पेशल व्यंजन का स्वाद चखाया जाएगा। दाल बाफला-दाल

बाटी के साथ ही नर्मदापुरम की स्पेशल डेजर्ट मावा बाटी विशेष रूप से सर्व की जाएगी। इसे 100 प्रतिशत मावा से बनाया जाता है। इसके अलावा बघेलखंड की खास इंद्रहार की कढ़ी की परोसी जाएगी। इसे पांच तरीके दाल को मिक्स करके बनाया जाता है। जिसे उबालकर उसे बर्फी के शेफ में काट कर कढ़ी में डाला जाता है। वहीं, मालवा की स्पेशल लाल भाजी भी स्पेशल डिस में रखी जाएगी। साथ ही मिलेट्स के भी दो आईटम रखे जाएंगे।

सम्पादकीय

अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार क्यों?

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि भारत ने अमेरिका के सामने अवैध रूप से वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपमानजनक तरीके से वापस भेजने का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12-13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भारतीयों को अपमानजनक तरीके से वापस भेजे जाने का मुद्दा उठा सकते हैं।

अमरीका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा है। वायुसेना के विमान के बजाय सामान्य यात्री विमान से उन्हें भेजा जा सकता था, क्योंकि सैन्य विमान का हमारी सरजमाँ पर उतरना देश की संप्रभुता के खिलाफ है। अमरीका में अवैध भारतीयों की संख्या करीब 7 लाख बताई जाती है। यदि राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन सभी को भारत वापस भेजना चाहेगा, तो पूरी कवायद में 10 साल लगेंगे। यह विशेषज्ञों का आकलन है। कानूनी औपचारिकताएं अलग हैं। अभी तक अमरीका में बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को ही विहित किया जा सका है। वे सभी अवैध प्रवासी हैं। वे अंतिम 'बेदखली आदेश' का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से 17,940 भारतीय ऐसे हैं, जो बाहर में घूम-फिर रहे हैं। हालांकि कड़ियों के पैरों में 'डिजिटल टै:कर' लगाए गए हैं, लिहाजा उनकी लोकेशन पर 'इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट' (आईसीई) चौबीसों घंटे निगाह रखती है। उधर 2467 अवैध भारतीय प्रवासी 'हिरासत केंद्र' में कैद हैं। उनमें से ही 104 को भारत वापस भेजा गया है। ऐसे अवैध प्रवासियों को 2009 से ही वापस भेजा जा रहा है, लेकिन जिस तरह सैन्य विमान से हथकड़ी बांधकर और पांवों में बेड़ियां पहना कर इन भारतीयों को वापस लाया गया है, वह 'अमानवीय' कृत्य है और आतंकियों के साथ किए गए व्यवहार सरीखा है। अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस छोड़ कर आना अमरीका की सरकारी नीति है, लेकिन प्रवासियों को लाते हुए ऐसा पाशविक व्यवहार क्यों किया गया? आज आम भारतीय यह सवाल पूछ रहा है और भारत-अमरीका संबंधों की सच्चाई जानना चाहता है। भारत अमरीका का मित्र-देश है, सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, क्या ऐसे देश के मूल नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार करना उचित है? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में वक्तव्य देकर कहा कि अब तक 15,756 अवैध भारतीय प्रवासी भारत लौटे हैं। यह सिलसिला कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के दौरान भी जारी था और मौजूदा सरकार के कालखंड में भी लगातार हर साल ऐसे भारतीय लौटे हैं। क्या विदेश मंत्री का इतना आश्वासन ही पर्याप्त है कि भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के लगातार संपर्क में है और आग्रह कर रहे हैं कि भारतीयों के संग ऐसा दुर्व्यवहार न हो। सवाल हथकड़ी-बेड़ियों वाले अमानवीय सलुक का है, जो हरेक आतंकवादी के साथ भी नहीं किया जाता। यदि कोलंबिया जैसे छोटे देश का राष्ट्रपति लाल आंखें दिखा कर अमरीकी विमान के उतरने से साफ इनकार कर सकता है, तो भारत जैसा मजबूत और विराट देश क्यों नहीं कह सका कि हम अपना विमान भेजकर ऐसे भारतीयों को वापस ले आएं? इस 'आंख से आंख मिलाने वाली' नीति से कूटनीति का कहां नुकसान हो रहा था? विदेश मंत्री एस. जयशंकर की तरफ से संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान दिए जाने के एक दिन बाद, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि भारत ने अमेरिका के सामने अवैध रूप से वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को अपमानजनक तरीके से वापस भेजने का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12-13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भारतीयों को अपमानजनक तरीके से वापस भेजे जाने का मुद्दा उठा सकते हैं। मिसरी ने कहा कि हां, भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया है। भारतीयों को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारना पहले की कार्रवाइयों से 'थोड़ा अलग' था। ट्रंप प्रशासन ने इसे मामला सिन्थीयोरिटी ऑपरेशन माना था इसलिए यात्रियों को अलग ढंग से लाया गया। शायद यही वजह रही कि यात्रियों के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। मिसरी ने कहा कि अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ जो व्यवहार हुआ उसे टाला जा सकता था।

प्रवेश, आशीष और सतीश...

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए कई नाम रेस में हैं। बताया जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री चुने गए विधायकों में से ही कोई होगा। हालांकि पार्टी इससे पहले तमाम फैक्टर्स पर भी गौर कर रही है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में जातिगत संतुलन को भी देखा जा रहा है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता आदि के नाम चल रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ-साथ डिप्टी सीएम भी रखने की चर्चा है। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि नया मुख्यमंत्री चुने गए विधायकों में से ही कोई बने। हालांकि इस फैसले में हफ्तेभर का समय लग सकता है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि इससे पहले ही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा चर्चा प्रवेश वर्मा के नाम पर है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने के साथ उन्होंने पुष्पा दावा पेश किया है। अपना विजयी सर्टिफिकेट लेने से पहले वर्मा ने दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। प्रवेश वर्मा एक जाट नेता हैं और दिल्ली की 10 फीसदी आबादी

का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनकी पकड़ काफी मजबूत है। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में आशीष सूद भी एक अहम नाम हैं। वे भाजपा में एक प्रमुख पंजाबी चेहरा हैं। आशीष सूद ने अपनी सियासी यात्रा एबीवीपी के साथ शुरू की और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। फिलहाल वे गोआ में पार्टी के मामलों को देखते हैं साथ ही उनके ऊपर जम्मू और कश्मीर की भी जिम्मेदारी है। भाजपा दिल्ली कैबिनेट में एक सिख चेहरे को भी शामिल कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह, सिरसा पहली पसंद बताए जा रहे हैं। वहीं, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में हराने वाले तरविंदर सिंह मारवाहा भी एक अन्य दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कम से कम एक महिला विधायक भी कैबिनेट में शामिल हो सकती है। इसके लिए शिखा राय, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान के नाम चर्चा में हैं। चार एससी विधायकों को भी दिल्ली सरकार में मौका दिया जा सकता है। प्रवेश वर्मा, पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। पश्चिमी दिल्ली से लगातार दो बार सांसद रहे। 2019 में उन्होंने 5.78 लाख वोट से चुनाव जीता, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। इस बार नई दिल्ली सीट से उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 4099 वोट से

गढ़ भी नहीं रहा और सेनापति भी नहीं

मराठी की एक कहावत में गढ़ जीतने को अहम तो बताया गया है, लेकिन गढ़ की जंग में अगर सेनापति का बलिदान हो जाता है तो उस जीत को भी बड़ा नहीं माना जाता। इसी मराठी कहावत की तर्ज पर दिल्ली की सियासी जंग को अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में देखें तो कह सकते हैं कि गढ़ तो गया ही, सिंह यानी सेनापति भी नहीं रहा। अलग तरह की वैकल्पिक राजनीति और उसके जरिये आम लोगों को खुशहाल और नए तरह के भविष्य का सपना दिखाकर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा में बहुमत एक तरह से गढ़ यानी किला ही था।

मराठी की एक कहावत में गढ़ जीतने को अहम तो बताया गया है, लेकिन गढ़ की जंग में अगर सेनापति का बलिदान हो जाता है तो उस जीत को भी बड़ा नहीं माना जाता। इसी मराठी कहावत की तर्ज पर दिल्ली की सियासी जंग को अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में देखें तो कह सकते हैं कि गढ़ तो गया ही, सिंह यानी सेनापति भी नहीं रहा। अलग तरह की वैकल्पिक राजनीति और उसके जरिये आम लोगों को खुशहाल और नए तरह के भविष्य का सपना दिखाकर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा में बहुमत एक तरह से गढ़ यानी किला ही था। अरविंद केजरीवाल वह किला अब खो चुके हैं और उनके लिए चिंता की बात है कि खुद उनके साथ उनके सेनापति इस जंग में खेत रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि आंदोलन से उपजी राजनीति के दौर का खतमा तय है? अभी तो यह मान लेना कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन अतीत के उदाहरणों को देखें तो साफ लगता है कि केजरीवाल के लिए राह अब आसान नहीं रही। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ उभरी आम आदमी पार्टी ने अलग तरह की राजनीति देने का वादा किया था। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर लोगों को कितनी उम्मीदें थीं कि अन्ना का अनशन तो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन उसके समर्थन में राजस्थान के रेतीले इलाकों में इक्का-दुक्का घरों के साथ बसी ढाणियों, झारखंड-छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों, पानीपत से लेकर मोतिहारी, कच्छ लेकर अरूणाचल प्रदेश तक, शायद ही कोई शहर या गांव रहा होगा, जहां मोमबतियां न जली हों। ये मोमबतियां दरअसल नए भारत की अंजोरियाभरी राह का सपना थीं। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि उसके जरिये देश और उनकी जिंदगी में ऐसा प्रकाश फैलेगा, जिसमें उनके, उनकी संततियों और उनके देश का भविष्य उज्वल होगा। इस उम्मीद और सपने को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने भरपूर साथ दिया। पहली 54.3 प्रतिशत वोट और 67 सीटों तो दूसरी बार 53.57 प्रतिशत वोट और 62 सीटें देना एक तरह से बेहतर और चमकीले सपनेलिे भविष्य को लेकर जनाकांक्षाओं का उफान था। कभी बंगला और गाड़ी न लेने, वीआईपी कल्चर को न अपनाने के वायदे के साथ राजनीति में आए केजरीवाल धीरे-धीरे इसी जनाकांक्षा को भूलते चले गए। दूसरे कार्यकाल में तो वे तानाशाह की तरह खुद को स्थापित करते गए। झूठ और फरेब की राजनीति की ही उन्होंने अपनी सियासी आदत बना लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भारी जीत के बाद जैसे उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। आम आदमी पार्टी में सिर्फ उनकी ही चलती थी। लोकतंत्र का मुखौटा भी वहां नहीं रह गया



था। वैसे भी आम आदमी पार्टी को पहली आर्थिक मदद देने वाले प्रशांत भूषण, वैचारिक आधार तैयार करने वाले योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ ही अपने साथी रहे कुमार विश्वास को वे पार्टी से पहले ही बाहर कर चुके थे। उनके साथ रहे उनके आंदोलन के दिनों के साथी मनीष सिसोदिया और स्वाति मालीवाल। हालांकि उनके शासन के आखिरी दिनों में जिस तरह स्वाति की मुख्यमंत्री के घर में ही पिटाई हुई, उसने केजरीवाल के स्वभाव की एक तरह से कलाई खोल दी। केजरीवाल ने अपने पहले कार्यकाल में बेशक अच्छे कार्य किए। मोहल्ला क्लीनिक का विचार दिया और उसे लागू किया। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया, दो सौ यूनिट तक बिजली और एक सीमा तक पानी मुफ्त दिया। महिलाओं को फ्री में बस यात्रा की सहूलियत दी। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। दो साल पहले के चुनाव में नगर निगम पर भी उनका कब्जा हो गया। इसके पहले दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम पर अपना नियंत्रण न होने का बहाना बनाते रहे थे, लेकिन अब वह बहाना भी नहीं रहा। फिर भी दिल्ली गंदी होती चली। दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाने वाली डीटीसी के बेड़े से बसें कम होती चली गईं। केजरीवाल के दौर में हवा-हवाई घोषणाएं खूब हुईं। इसकी वजह से उनसे फायदा लेने वाले लोग भी खुश नहीं थे। डीटीसी के कर्मचारियों, बसों में तैनात मार्शलों आदि को स्थायी नौकरियां देने का वादा कर चुके केजरीवाल उन्हें नौकरियां नहीं दे पाए। शुरू में उनकी बहानेबाजी तो चली,लेकिन बाद में लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि वे सिर्फ हवा-हवाई दावे करते हैं और बहानेबाजी के जरिये खुद को बचा ले जाते हैं। 2022 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने महिलाओं को हजार रुपए महीने देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें यह रकम नहीं दे पाए। पंजाब रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री सहूलियत देने के चलते पंजाब रोडवेज घाटे में है। इसकी वजह से महीनों तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। सूचना और संचार क्रांति के दौर में ये सारी बातें दिल्ली की जनता तक पहुंचती रहीं। इसका असर यह हुआ कि केजरीवाल से लोगों का भरोसा खत्म हो गया। पिछले दो चुनावों तक केजरीवाल नैरेटिव तैयार करते थे और उनके विपक्षी उसका जवाब देते थे। इस बार भी महिलाओं को 21 सौ रुपए महीने देने और उसके लिए उनके फॉर्म भरवाकर नैरेटिव स्थापित कर दिया था। लेकिन बाद में बीजेपी ने उनकी काट शुरू की। उसने अपना पंथ सृष्टीय संकल्प पर पेश किया। महिलाओं को 2500 रुपए महीने की सम्मान निधि देने और 200 की बजाय 300 यूनिट बिजली फ्री देने जैसे ऐलान किए। इसका असर वोटों पर दिखा। इस बीच बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन के लिए अपने सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री

उतार दिए। मंडल स्तर तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी सक्रिय हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बुनियादी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, जिन्हें मनाने की जरूरत थी, उन्हें मनाया, सबके योग्य जिम्मेदारी दी। सभी कार्यकर्ता सक्रिय हुए। उन्होंने जमीनी स्तर तक काम किया। इसका असर चुनावों में दिखा। केजरीवाल की पार्टी पस्त रही। खुद केजरीवाल भी हारे हैं, उनके विश्वस्त मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राखी बिड़लान जैसे नाम चुनावी जंग में खेत रहे हैं। बीजेपी की जीत में कुछ हिस्सेदारी कांग्रेस भी है। हालांकि उसे पिछले चुनाव की तुलना में महज दो फीसदी ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को भले ही समर्थन नहीं मिला। कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार और उनके बड़बोलेपन के खिलाफ माहौल बनाने में योगदान जरूर दिया। दिल्ली की सूरत बदलने वाली शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने खुलेआम मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने कहा था कि अपनी मां के अपमान का बदला वे जरूर लेंगे। संदीप खुद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से मैदान में उतरे और केजरीवाल की हार की पटकथा लिखने में मदद की। कांग्रेस ने भी मान लिया है कि उसका असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी की बजाय आम आदमी पार्टी है। इसलिए उसने अपना सारा ध्यान आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ रखा। केजरीवाल के शीश महल का सवाल भले बीजेपी ने उठाया, लेकिन जिस आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल जेल गए थे, उसका भंडाफोड़ कांग्रेस के नेता अजय माकन ने ही किया था। जनता के बीच वे सादगी के साथ आए थे, इसलिए लोगों को उनका शीश महल स्वीकार नहीं हुआ। केजरीवाल ने चुनाव के आखिरी वक्त में एक और गलती कर दी। उन्होंने यह कहकर बीजेपी पर हमला बोला कि उसकी हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है ताकि दिल्ली वालों का नुकसान हो। इस बात को जनता स्वीकार नहीं कर पाई। जनता ने माना कि केजरीवाल का भी यह ही एक बहाना है, उस वायदे को ढकने के बहाना है, जिसके तहत उन्होंने यमुना को पांच साल में साफ करने और उसमें नहाने का वादा किया था। दिल्ली में राजनीतिक माहौल बदल चुका है। अब बीजेपी के सामने जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह राजधानी को खुशहाल ही नहीं, पर्यावरण अनुकूल और साफ भी बनाए। केजरीवाल के लिए यह चिंतन का वक्त है। उनका गढ़ भी छिन गया है और सेनापति भी नहीं रहे। ऐसे में सेना का उठ खड़ा होना आसान नहीं, वे उठ पाएंगे या नहीं, उनकी राजनीति में बदलाव आएगा या नहीं, यह तो वक्त ही बता पाएगा।

दिल्ली का नया सीएम बनने की रेस में

नाम भी सीएम रेस में चल रहा है। इस सीट पर उनका मुकामला आम आदमी पार्टी के विशेष रवि और थोड़ी। वहीं सास नीना वर्मा और ससुर विक्रम वर्मा भी दामाद प्रवेश वर्मा का प्रचार करने दिल्ली गए थे। अभी भी दोनों दिल्ली में ही हैं। साल 2002 में प्रवेश वर्मा की स्वाति वर्मा से शादी हुई। इनके एक बेटा शिवेन और दो बेटियां सानिधि और प्रिशा हैं। ससुर विक्रम वर्मा अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उस दौरान प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम थे। प्रवेश वर्मा का जन्म 1977 में हुआ था। उन्होंने स्कूलिंग आरकेपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की। उन्होंने एमबीए किया है। स्वाति ने भी पुणे से एमबीए किया है। वो बिजनेस बुनेन होने के साथ ही सोशल वर्क भी करती हैं। 2023 में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में सास नीना वर्मा के प्रचार के लिए प्रवेश वर्मा खुद धार आए थे। इस चुनाव में लगातार चौथी मर्तबा धार से नीना वर्मा को जीत मिली थी। प्रवेश के साथ उनकी पत्नी स्वाति भी धार विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बैठक लेने और पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंची थीं। चुनाव के अलावा भी प्रवेश धार आते रहते हैं, इसी कारण स्थानीय नेताओं से भी प्रवेश वर्मा का सीधा संपर्क है। दिल्ली के करोल बाग विधानसभा चुनाव से बीजेपी उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम का

पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रेखा शालीमार बाग से चुनाव लड़ीं। 2020 में वे मामूली अंतर से हार गई थीं। उधर, शिखा राय ग्रेटर कैलाश से आप के सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी थीं। यदि भाजपा नया चेहरा लाई तो आप के नेता रहे कपिल मिश्रा अब भाजपा के प्रमुख हिंदुत्व चेहरा हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। एक समय वे केजरीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे, लेकिन अब भाजपा के दिल्ली उपाध्यक्ष हैं और करावल नगर से चुनाव जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख और मजबूत हिंदुत्व अपील उन्हें संभावित सीएम उम्मीदवार बनाती है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत बिजवासन से चुनाव जीत गए हैं। वे भाजपा में शामिल होने से पहले आप के टिकट पर दो बार नजफगढ़ से जीते थे। एक मंत्री के रूप में उनका अनुभव उन्हें एक महत्वपूर्ण पद के लिए दावेदार बना सकता है। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली को मुख्यमंत्री के नाम पर भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। एक बार जब पार्टी सीएम के लिए नाम तय कर लेती है तो भारत के राष्ट्रपति, उपराज्यपाल की सलाह पर सीएम की नियुक्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। उधर, पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना तय है। पीएम मोदी को 12-

13 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक के लिए अमेरिका भी जाना है। इससे पहले वे फ्रांस का दौरा भी करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद यह शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली के सीएम और मंत्रिमंडल के नाम पर मुहर बीजेपी का आलाकमान ही लगाएगा। भाजपा मंत्रिमंडल और सीएम फेस के जरिये दिल्ली और देश की राजनीति में जातिगत और राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। किसी नए नाम को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि सीएम नहीं बन पाने वाले दिल्ली के तमाम बड़े दिग्गजों को कम से कम मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सवाल यह भी है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार के शपथग्रहण में कौन-कौन लोग शामिल होगा। पीएम मोदी और अमित शाह का शपथ ग्रहण में शामिल होना तय माना जा रहा है। बीजेपी के तमाम प्रदेशों में सीएम को भी इस समारोह में आमंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीद इस बात की भी है कि अरविंद केजरीवाल को भी नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। अब तय भाजपा को करना है कि वह सीएम चुनते समय किस पहलू को ज्यादा तवज्जो देती है। अनुभव, हिंदुत्व चेहरा, संघ से कनेक्शन, नया चेहरा, महिला या फिर भाजपा कोई प्रयोग करना चाहेगी, जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी।

आपरेशन मुस्कान के तहत थाना नारायणगढ़ पुलिस ने अपहृता को किया दस्तयाब

मंदसौर- पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे नाबालिक बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के संबंध में मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। जिला मंदसौर में अपहृत हुयी नाबालिक बालिकाओं की बरामदगी हेतु अभिषेक आनंद पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा दिए गए निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल रघुवंशी व उनकी टीम के द्वारा थाना नारायणगढ़ के अप.क्र. 17/2025 धारा 137 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहृत हुयी नाबालिक बालिका को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। घटना का विवरण: घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 22.01.2025 को फरियादी द्वारा थाना नारायणगढ़ पर अपनी नाबालिक बालिका आयु 16 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट पर थाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप. क्र. 17/25 धारा 137 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया तथा प्रकरण के अनुसंधान के दौरान सायबर सेल व विश्वसनीय मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल टीम गठित कर बालिका को भादवा माता जिला नीमच से दस्तयाब किया गया बालिका से पुछताछ करते अपने साथ किसी प्रकार की घटना नहीं होना बताया बाद बालिका को उसके माता-पिता को सुपुर्द किया गया। पुलिस टीम:- उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अनिल रघुवंशी थाना प्रभारी नारायणगढ़, उनि भारत भाबर, प्रआर आशीष बैरागी (सायबर सेल), प्रआर 164 अनुप सिंह, आर. मनीष बघेल (सायबर सेल), आर. 856 दीपक पाटीदार, आर. 874 आनन्द मालवीय, आर. 393 उदल सिंह, मआर नीतु पाटीदार, आर. 689 हुकुमसिंह, की सराहनीय भूमिका रही।

प्रत्याशियों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा किए गए चुनाव चिन्ह आवंटित

बरेली। बरेली हिंदू उत्सव समिति बरेली के चुनाव मैदान में छह अध्यक्ष प्रत्याशी सहित अन्य पदों के प्रत्याशी उतर चुके हैं। दोपहर समय रामलीला मैदान पर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा चुनाव लड़ने वाले समस्त पदों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। यह पहला अवसर है जब समिति के अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में उठे हुए हैं सामाजिक समीकरण और समाजवाद का असर इस चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है अभी भी कई प्रत्याशियों को उम्मीद है कि समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी आपसी सामंजस्य बनाकर शायद अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी की घोषणा कर दें, लेकिन यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि कोई भी राजनीतिक या समिति के वरिष्ठ के द्वारा अब इस चुनावी समर में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा समिति में अध्यक्ष पद हेतु लड़ रहे 6 प्रत्याशियों में से चार ब्राह्मण समाज से हैं बाकी दो प्रत्याशी अन्य समाजों से आते हैं अब देखना यह है कि ब्राह्मण समाज के



किसी प्रत्याशी को मतदाता अपना समर्थन देते हैं या फिर इस समाज से हटकर अन्य समाज की तरफ उनका मत जाता है। बरेली हिंदू उत्सव समिति में 700 मतदाता अपने मतों का

उपयोग करते हैं लेकिन इन मतदाताओं में से कई मतदाता तो चुनावी समर में भाग ही नहीं लेते कभी भी समिति के चुनाव में पूरे मतों का उपयोग नहीं किया जाता मतदान का

प्रतिशत हर चुनाव में गिरता है लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद पिछली बार के प्रतिशत से भी अधिक प्रतिशत मतदान इस चुनाव में हो सकता है।

बुरहानपुर में ड्रोन से खेतों में दवा का छिड़काव



बुरहानपुर - नेपानगर क्षेत्र के ग्राम अंबाड़ा में किसान अब आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग कर फसलों में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं जो न केवल समय की बचत कर रहा है बल्कि किसानों के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रहा है सारोला गांव के किसान मनोज प्रहलाद महाजन ने बताया कि ड्रोन से एक एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव मात्र 15 मिनट में हो जाता है पहले जहां किसानों को तेज धूप में पीट पर पंप लेकर घंटों मेहनत करनी पड़ती थी वहीं अब ड्रोन से एक समान और प्रभावी छिड़काव होता है इस सेवा के लिए किसानों को प्रति एकड़ मात्र 2400 का भुगतान करना होता है कृषि विभाग के संचालक मनोहर सिंह देवके ने बताया कि ड्रोन तकनीक से न केवल कीटनाशक छिड़काव बल्कि फसल निगरानी भी की जा रही है साथ ही यह तकनीक स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर बन गई है।

फोन पर लेते हैं बुकिंग क्षेत्र के एकमात्र ड्रोन संचालक लखन पवार ने बताया कि वह सुबह 6:00 से शाम 6:00 बजे तक सेवाएं प्रदान करते हैं वे फोन कॉल पर बुकिंग लेते हैं और अपनी गाड़ी में ड्रोन लेकर खेतों तक पहुंचते हैं युवाओं को भी ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे भविष्य में और अधिक किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

अग्निहोत्र कृषि संगोष्ठी का आयोजन

कांटाफोड़ - ग्राम जिनवानी में अग्निहोत्र कृषि पर आधारित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माधव आश्रम भोपाल से पथारे डा विवेक पोतदार व अन्य लगभग 150 जागरूक किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम में बाँरे खर्च प्राकृतिक रूप से खेती कैसे की जाए इस विषय पर अपने अपने विचार रखे तथा इस कार्यक्रम की



विशेषता यह रही की कार्यक्रम का आयोजन उसी खेत में रखा गया जहां पूर्व से अग्निहोत्र पद्धति की कृषि की जा रही है उपस्थित युवाओं ने यह तय किया की आगामी समय में वह रसायनिक खेती न कर अग्निहोत्र कृषि करेंगे कार्यक्रम में दीपक राव जयनारायण राय गुड्डू सोनी गोविन्द बारवाल जेपी मीणा व अन्य कृषक उपस्थित थे।

सायबर जागरूकता हेतु सेफ क्लिक अभियान

सेफ क्लिक अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नीमच द्वारा सोशल मिडिया पर सायबर फ्राड जागरूकता हेतु अपील की प्रसारित

थाना क्षेत्रों ग्राम चैपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन

नीमच- पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 11.02.2025 को सेफ इन्टरनेट दिवस के परिपेक्ष्य में समाज में सायबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 01/02/2025 से दिनांक 11/02/2025 तक (सायबर सुरक्षा जागरूकता) 'सेफ क्लिक अभियान' चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन (भापुरे) एवं उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद सुश्री निकीता सिंह के मार्गदर्शन में जिले के समस्त पुलिस थानों में पुलिस टीम द्वारा वृहद स्तर पर स्कूल, कॉलेज में छात्र-छात्राओं और



सार्वजनिक स्थानों पर आमजन को सायबर फ्राड से बचने के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.02.2025 को पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल द्वारा आमजन को सायबर फ्राड - डिजिटल अरेस्ट, लोन एप फ्राड, केवायसी अपडेट फ्राड, अनजान विडियो कॉल फ्राड, ओएलक्स फ्राड आदि से

जागरूक करने हेतु अपील सोशल मिडिया पर प्रसारित की गई है। अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.02.2025 को थाना नीमच कैंपेण्ट अंतर्गत ग्राम कनावटी एवं गाड़ौलिया बस्ती कनावटी, थाना नीमच सिटी अंतर्गत सिलिकॉन फेक्ट्री नीमच सिटी, थाना बघाना अंतर्गत होली चोक बघाना, थाना जावद अंतर्गत कस्बा जावद, थाना रतनगढ़ अंतर्गत सामुदायिक भवन रतनगढ़, आंगनवाड़ी जाट, थाना कुकड़ेश्वर अंतर्गत बस स्टैण्ड कुकड़ेश्वर, थाना परिसर कुकड़ेश्वर, थाना रामपुर अंतर्गत बस स्टैण्ड रामपुर पर सीम स्वेप फ्राड, केवायसी फ्राड आदि की जानकारी एवं बचाव संबंधी पोस्टर एवं पेम्पलेट्स वितरित कर ग्राम चैपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन, महिलाओं को जागरूक किया गया।

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने नागेश पांडे उपाध्यक्ष बालेंद्र सिंह.

बैरसिया-- मध्यप्रदेश शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी के चुनाव प्रांतीय अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौर के तत्वाधान में संपन्न हुए। जिसमें सर्वसम्मति से शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नागेश पांडे बनाए गए साथ ही उपाध्यक्ष डॉ.आर के यादव, जिला उपाध्यक्ष नेतुल बालेंद्र सिंह जिला सचिव योगेश सकसेना को मनोनीत किया गया। बालेंद्र सिंह ने



कार्यकारिणी का आधार प्रकट करते हुए उन्हें आश्वस्त किया है कि वे सदैव संगठन के हित में पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करते हुए कर्मचारी हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। इस मौके पर उपस्थित शिक्षक संघ के साथियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पमाला से स्वागत कर शुभकामनाएं दीं।

पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में सेफ क्लिक सायबर जागरूकता अभियान के तहत पुलिससायबर जागरूकता

अलीराजपुर- पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में सेफ क्लिक सायबर जागरूकता अभियान के तहत पुलिस कप्तान राजेश व्यास व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन में जिला अलीराजपुर पुलिस द्वारा थाना आम्बुआ ग्राम कोटवू में उनि. मोहन डावर, सर्जनि. विजय वर्मा, आर.466 गिरीधारी, आर.431 राजेश भूरिया के द्वारा सायबर जागरूकता कार्यक्रम

आयोजित कर ग्रामिण नागरिकों को पहचान चोरी, सुरक्षित ब्राउजिंग और ऑनलाइन वित्तिय लेनदेन संबंध में जानकारी दी गई और सायबर अपराध से बचने के लिए जागरूक किया गया। थाना सोरवा मेथाना सोरवा में उनि. दिलीप चन्देल, सर्जनि. कान्तिपाल मावी, मप्रआर.258 हिरा रावत, मआर.416 रज्जू द्वारा ग्रामिण क्षेत्र के नागरिकों को पहचान चोरी, सुरक्षित ब्राउजिंग और ऑनलाइन

वित्तिय लेनदेन संबंध में जानकारी दी गई और सायबर अपराध से बचने के लिए जागरूक किया गया। अलीराजपुर पुलिस सायबर सेल हेल्पलाईन नम्बर-7587616701 अलीराजपुर पुलिस सायबर सेल ई-मेल आईडी- sp_alirajpur@mppolice.gov.in Ministry of Home affairs Cyber Crime हेल्पलाईन नम्बर-1930



सेफ क्लिक अभियान जैन मुनि का हुआ नगर आगमन

झाबुआ पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा 01 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा अभियान सेफ क्लिक के तहत मध्यप्रदेश के सभी जिलों में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक झाबुआ पंचविलोचन शुक्ल के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे के मार्गदर्शन में रक्षा सखी टीम, साइबर टीम व समस्त थानों के पुलिस अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा आमजन के बीच जाकर उन्हें लगातार साइबर सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक



बाग - आचार्य श्री ऋषभचंद्र सूरि जी के शिष्यरत्न पीयूषचंद्र विजय जी व रजतचंद्र विजय जी महाराज साहब का यहां शुभआगमन हुआ। जैन श्रीसंघ बाग, म.सा. की, बाघनी नदी के समीप अगवानी करने पहुंचा। ढोल-ढमाके के साथ उत्साह से नगर भ्रमण कर विमलनाथ जैन मंदिर पहुंचा व प्रभु का सामूहिक चेत्यवंदन किया। पश्चात पुण्यसम्राट हाल में प्रवचन में बताया की संतो व बसंत के आगमन से ईसान एवं प्रकृति में पुण्य - हर्ष - प्रसन्नता छा जाती है। जीवन को संतो के सानिध्य में एवं बसंत की तरह खुशी से गुजारो। दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्या है। मन का भाव (भावना) सही हो तो वर्तमान भव सुधरता है। कोई भी व्यक्ति मुझा हुआ फूल नहीं

चाहता सभी खिला हुआ फूल चाहते हैं। संघ-समाज चाहे छोटी संख्या में हो मन उदार-विराट होना चाहिए। गुरु के पास हमेशा चिंतामुक्त एवं खुश होकर जाना चाहिए। मुनिश्री ने बताया कि जब जीवन का अंत हो, मुख का नाम अरिहंत हो, सामने कोई संत हो व वर्धमान महावीर स्वामी का पंथ हो। गुरु को वंदन करने से जीवन के बंधन टूटते हैं। आपश्री ने बताया की मुंबई के जिला पालघर के दहाणु (घोलवड़) से श्री राजेन्द्रसूरी तीर्थ धाम में गुरुसममी कार्यक्रम संपन्न कर अभी निसरपुर (कुक्षी) में जैनों के 22वें तीर्थंकर यदुवंशी श्री नेमनाथ - राजुल मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न कर यहां विहार किया। समाज के अरविंद जैन ने बताया की बाग श्री संघ के अध्यक्ष

ब्रिटेन में चीन के नए दूतावास को लेकर फूटा गुस्सा, लंदन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन

इंटरनेशनल डेस्क. ब्रिटेन में चीन के नए दूतावास को लेकर लंदन में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हजारों लोग इसके स्थानांतरण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह विशाल दूतावास मानवाधिकारों और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर सकता है। चीन कई वर्षों से अपने दूतावास को लंदन के ऐतिहासिक स्थल टॉवर ऑफ लंदन के पास स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो यह यूरोप में सबसे बड़ा चीनी दूतावास होगा। फिलहाल, यह दूतावास मैरीलेबोन जैसे पॉश इलाके में स्थित है, लेकिन इसे स्थानांतरित करने की योजना पर लोग नाराज हैं।

ब्रिटेन के छाया मंत्री और विपक्षी कंजरवेटिव पार्टी के सांसद उन सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में शामिल रहे, जो पूर्वी लंदन में चीन के तथाकथित 'विशाल दूतावास' के प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित हुए। छाया न्याय मंत्री रॉबर्ट जेनरिक, छाया सुरक्षा मंत्री टॉम टुंगदहट और पूर्व टोरी नेता इयान डंकन स्थित शनिवार को 'टॉवर ऑफ लंदन के पास ऐतिहासिक रॉयल मिंट कोर्ट स्थल पर हांगकांगवासियों, उड़गों और तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों के साथ शामिल



हुए। छाया मंत्री विपक्ष के सदस्य होते हैं, जो सरकार के काम की निगरानी करते हैं।

ब्रिटेन की मीडिया में आई खबरों के अनुसार, प्रदर्शनकारी एक बहुत बड़े नए दूतावास के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, जिसके बारे में उन्हें डर है कि अगर इसे यूरोप में चीन के सबसे बड़े राजनयिक मिशन में से एक के रूप में आगे बढ़ने की अनुमति दी गई तो इसका इस्तेमाल 'जासूसी

केंद्र के रूप में किया जा सकता है। जेनरिक ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, 'हम नहीं चाहते कि हमारे पीछे स्थित यह ऐतिहासिक इमारत - टॉवर ऑफ लंदन के पीछे - चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा दूतावास बन जाए। पूर्व आवास मंत्री ने कहा, 'यह गलत स्थान है। यह गलत प्रक्रिया है और यह हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।

विशेषज्ञों की गंभीर चेतावनी-

मक्का मदीना वाले देश पर मंडरा रहा खतरा ! ज्यादा बच्चे पैदा न किए तो...

इंटरनेशनल डेस्क. दुनिया के कई देश घटती जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे हैं। चीन और जापान के बाद अब एक मुस्लिम देश भी इसी संकट से जूझ रहा है। इस लिस्ट में खाड़ी देश सऊदी अरब उभर कर सामने आया है। दुनियाभर से लोग यहां पैसा कमाने जाते हैं लेकिन पवित्र मक्का मदीना वाला यह देश जन्म दर गिरने कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकता है। ये चेतावनी देते हुए विशेषज्ञ व सऊदी लेखक मंसूर अल दबान कहा है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में सऊदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। उनके लेख में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला दिया गया, जिसमें दर्शाया गया कि 1950 की तुलना में 2023 तक सऊदी अरब में जन्म दर में 67 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के विशेष उपायों पर ध्यान न दिया तो यह संकट देश के अस्तित्व पर भारी पड़ सकता है। 1950 में प्रति 1,000 लोगों पर जन्म दर 53.34 थी, लेकिन 2023 तक यह गिरकर 15.7 हो गई। केवल 2022 से 2023 के बीच ही इसमें 2.88 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो अत्यंत चिंताजनक है। मंसूर अल दबान ने यूएई के शारजाह विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन अरब दुनिया में मानव प्रजनन दर में महामारी संबंधी गिरावट का भी हवाला दिया। इस अध्ययन में 2011 से 2021 तक अरब देशों की प्रजनन दर का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि लगभग सभी अरब देशों में जन्म दर घट रही है।



उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो 2100 से पहले ही सऊदी जनसंख्या गंभीर संकट में आ सकती है। उन्होंने इस समस्या के लिए शादी में देरी, बच्चों के जन्म में देरी, शादी से बचने की प्रवृत्ति और बढ़ती बांझपन को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी सरकार के जनरल अर्थो रिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 35 मिलियन से अधिक हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 के मध्य तक सऊदी अरब की जनसंख्या 35.3 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.6 मिलियन की वृद्धि होगी। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इस वृद्धि का केवल 24.4 प्रतिशत ही सऊदी नागरिकों से आया है, जबकि बाकी वृद्धि प्रवासी आबादी की वजह से हुई है। प्रजनन दर में भारी गिरावट 2024= प्रति 1,000 महिलाओं

पर 2.7 जन्म 2011= प्रति 1,000 महिलाओं पर 3.8 जन्म जबकि गैर-सऊदी महिलाओं की जन्म दर 2024 में प्रति 1,000 महिलाओं पर 0.8 जन्म रही। ह साफ दर्शाता है कि सऊदी नागरिकों की जन्म दर तेजी से घट रही है, जबकि प्रवासी आबादी में वृद्धि हो रही है। क्या हैं कारण? अधिकांश महिलाएं उच्च शिक्षा और करियर पर ध्यान दे रही हैं, जिससे शादी की उम्र बढ़ रही है। लोग पारंपरिक रूप से जल्दी शादी करने से बच रहे हैं, जिससे जन्म दर प्रभावित हो रही है। सऊदी अरब में महंगाई बढ़ रही है और परिवार पालना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। स्वास्थ्य कारणों और जीवनशैली में बदलाव के चलते प्रजनन दर प्रभावित हो रही है। नई पीढ़ी पहले की तुलना में छोटे परिवारों को प्राथमिकता दे रही है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो ... 2100 तक सऊदी नागरिकों की जनसंख्या अत्यधिक घट सकती है। देश में प्रवासियों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में बदलाव हो सकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कामकाजी सऊदी नागरिकों की संख्या कम होगी। इस खतरे से निपटने के लिए संभावित उपाय परिवार को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू करना। शादी और बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। महिलाओं और पुरुषों के लिए अनुकूल पारिवारिक वातावरण बनाना। प्रजनन स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना।

महिलाओं के लिए शानदार निवेश का मौका, महिला सम्मान बचत पत्र से मिलेगा बेहतरीन रिटर्न!

नेशनल डेस्क. आजकल निवेश करना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि आज के समय में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना बेहद जरूरी है। महिलाओं के लिए कई प्रकार की बचत योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन *महिला सम्मान बचत पत्र योजना* एक ऐसा निवेश विकल्प है, जो न केवल सुरक्षित है, बल्कि इससे अच्छा रिटर्न भी मिलता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है और 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। महिलाओं के वित्तीय सुरक्षा के लिए किया डिजाइन यह एक खास बचत योजना है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं के वित्तीय सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना में निवेश करने पर महिलाओं को 7.5% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो हर तीन महीने में उनके खाते में जमा होता है। इसका मतलब यह है कि हर तिमाही ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिससे निवेशक को नियमित रूप से आय प्राप्त होती है। महिलाएं अपने निवेश में प्राप्त कर सकती हैं बेहतर रिटर्न महिला सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये हैं, जो किसी भी महिला के लिए शुरू करना आसान है। वहीं, अधिकतम राशि 2 लाख रुपये तक निवेश की जा सकती है, जिससे महिलाएं अपने निवेश को बढ़ा सकती हैं



और बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना दो साल की अवधि के लिए है, यानी दो साल तक निवेश करने के बाद आपकी राशि और ब्याज वापस मिल जाएगा। आकर्षक और बेहतर रिटर्न देने वाला विकल्प महिला सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश पर 7.5% का ब्याज दर दिया जा रहा है, जो वर्तमान समय में एक आकर्षक और बेहतर रिटर्न देने वाला विकल्प है। यह ब्याज दर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। इसके साथ ही, इस योजना में हर तीन महीने में ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिससे निवेशकों को समय-समय पर पैसे का लाभ मिलता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए भी योजना इस योजना की एक और विशेषता यह है कि इसमें

18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए भी खाता खोला जा सकता है। इसके लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावक को खाता खोलने की अनुमति मिलती है। यह पहल छोटे बच्चों को भी वित्तीय सुरक्षा और बचत की आदत डालने में मदद करती है। योजना में निवेश करने पर महिलाओं को टैक्स बेनिफिट्स महिला सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश करने पर महिलाओं को टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यानी, इस योजना में निवेश करने से आपको टैक्स में राहत मिल सकती है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और बेहतर हो सकती है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना महिला सम्मान बचत पत्र योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना महिलाओं के लिए एक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रस्तुत करती है, ताकि वे भविष्य में किसी भी वित्तीय संकट से निपट सकें। बैंक में जाकर खाता खोलने की जरूरत महिला सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश करने के लिए आपको किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खाता खोलने की जरूरत होगी। खाता खोलते वक्त आपको अपनी पहचान और

श्रीलंका में एक बंदर ने पूरे देश में कर दिया अंधेरा ! घंटों परेशान रहे लोग

इंटरनेशनल डेस्क. श्रीलंका में एक अनोखी घटना सामने आई, जब एक बंदर के कारण पूरे देश में बिजली गुल हो गई। यह घटना रविवार (9 फरवरी 2025) को दक्षिण कोलंबो में हुई, जब एक बंदर ग्रिड ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया और इससे पूरे विद्युत सिस्टम में असंतुलन पैदा हो गया। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कुमार जयकोडी ने बताया कि इस घटना के चलते पूरे देश को तीन घंटे तक ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह लगभग 8:30 बजे ग्रिड ट्रांसफार्मर में बंदर घुसने के कारण अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे पूरे देश में अंधेरा छा गया और लोग असुविधा में पड़ गए। इंजीनियरों की तत्परता के चलते सुबह 11:30 बजे तक कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आपूर्ति पूरी तरह सामान्य होने में और समय लगा। यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंका को ऐसे बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ा हो। वर्ष 2022 में जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक



संकट से गुजर रहा था, तब देश में ईंधन की भारी कमी के कारण महीनों तक बिजली कटौती जारी रही थी। उस दौरान लोग 10 से 13 घंटे तक बिजली कटौती झेलने को मजबूर थे, जिससे व्यापार, स्कूल और अस्पतालों पर भारी असर पड़ा था। उस समय देश में खाद्य और ईंधन सहित कई आवश्यक चीजों की आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया था और सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। बंदरों द्वारा उत्पात मचाने की खबरों तो अक्सर सामने आती हैं, लेकिन इस बार श्रीलंका के राष्ट्रीय

ग्रिड को ठप कर देने की घटना ने सबको चौंका दिया। अधिकारियों ने बताया कि ग्रिड में घुसने वाला यह बंदर बच नहीं पाया, लेकिन उसके कारण पूरे देश को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। अब प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय कर रहा है। हालांकि, यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, और लोग इसे हनुमान जी द्वारा त्रेतायुग में लंका जलाने की पौराणिक कथा से जोड़कर मजाकिया टिप्पणियां कर रहे हैं।

बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता के घर पर हमले के बाद 40 लोग गिरफ्तार

इंटरनेशनल डेस्क. बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग के एक नेता के घर में तोड़फोड़ के दौरान एक छात्र समूह के कार्यकर्ताओं पर हुए हिंसक हमले के बाद बांग्लादेश में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद युनुस की सरकार ने शुक्रवार रात गाजीपुर जिले में छात्रों और आम लोगों पर हुए हमले के बाद शनिवार को ऑपरेशन डेविल हंट का आदेश दिया था। 'यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की खबर के अनुसार गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) चौधरी जावेर सादिक ने कहा कि



अभियान के तहत जिले के विभिन्न हिस्सों से 40 लोगों को पकड़ा गया। शुक्रवार की रात, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सभी चिह्नों को नष्ट करने और तोड़फोड़ करने वाली भीड़ के

कम से कम 14 लोग गाजीपुर शहर के दक्षिणखान इलाके में हमले की चपेट में आकर घायल हो गए। यह हिंसा पूर्व मुक्ति संग्राम मामलों के मंत्री मोजम्मेल हक के आवास पर हमले के दौरान हुई थी।

युद्ध विराम समझौते के तहत गाजा के प्रमुख गलियारे से इजराइली सेना की वापसी शुरू

इंटरनेशनल डेस्क. हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइली सेना ने गाजा के एक प्रमुख गलियारे से हटना शुरू कर दिया है। इजराइली अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। युद्धविराम समझौते के एक भाग के रूप में इजराइल ने नेत्ज़ारिम गलियारे से अपनी सेनाएं हटाने पर सहमति व्यक्त की थी। यह एक धूप-पट्टी है जो उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग करती है। इजराइली अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह बात कही, क्योंकि उन्हें मीडिया के साथ सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था। इजराइल ने युद्ध विराम की



शुरुआत में फिलीस्तीनियों को युद्धग्रस्त उत्तरी क्षेत्र में अपने घरों को ओर जाने के लिए नेत्ज़ारिम पार करने की अनुमति देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा क्षेत्र से सेनाओं की वापसी समझौते के प्रति एक और प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है

कि रविवार को इजराइल ने कितने सैनिक वापस बुलाये थे। बयालीस दिवसीय युद्ध विराम अभी अपने आधे पड़ाव पर है और दोनों पक्षों को इसे बढ़ाने के लिए बातचीत करनी है, जिससे हमास की कैद से और अधिक इजराइली बंधकों को मुक्त कराया जा सके।